दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

बचाव की तलाश में सरकार

राफाल सौदे की गुत्थी भाजपा की उम्मीदों से कहीं ज्यादा तेजी से सुलझती जा रही है। अगर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी ने यह सोचा हो कि बिना पारदर्शिता के हुई हाल की ज्यादातर रक्षा खरीदों पर परदा डाला जा सकता है, तो वह गलत थी। अब तो उन्हें बुरी हालत में सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। इसका बड़ा श्रेय 'द हिंदू' और उस प्रकाशन समूह के अध्यक्ष एन. राम को जाता है। हालांकि कुछ और महत्त्वपूर्ण लोग भी थे, और हैं, जो सरकार और उसके नेताओं के भारी दबाव के बावजूद पूरी ताकत से खड़े रहने के लिए बधाई के हकदार हैं।

नया और दोषपूर्ण सौदा

सबसे पहले तो उन तथ्यों पर गौर करें जिनका खुलासा हो चुका है।

1- अब यह साफ हो चुका है कि रफाल सौदा अकेले प्रधानमंत्री मोदी का किया हुआ है। मोदी ही इसके कर्ताधर्ता थे, इसे बड़ी ही चतुराई और सावधानी से अंजाम दिया गया, और सारे महत्त्वपूर्ण फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ही किए।

2- कुछ निश्चित कारणों की वजह से यूपीए के वक्त वाले सहमति पत्र को पहले खारिज न करने का फैसला किया गया था। पहले नया सौदा शुरू करने का फैसला हुआ, और चूंकि पूर्व का सहमति पत्र प्रभावी था, इसलिए उसे बाद में रद्द कर दिया गया।

3- फैसला करने वाले प्रमुख पक्षों- रक्षामंत्री, विदेश मंत्री, वायु सेना, रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) को बाहर रखा गया।

4-आठ अप्रैल, 2015 को पेरिस में विदेश सचिव ने मीडिया को बताया कि रफाल को लेकर दोनों सरकारों, दासो और हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी और भारत के प्रधानमंत्री तथा फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच होने वाली वार्ता के एजेंडे में रफाल का मुद्दा शामिल नहीं था। दो दिन बाद, दस अप्रैल को मोदी और ओलांद की बैठक में नए सौदे का एलान हो गया!

5- यह नया करार वास्तव में नया था। एक सौ छब्बीस विमानों का नहीं, सिर्फ छत्तीस विमानों का सौदा, जो पूर्व में निर्धारित कीमत पर नहीं बल्कि नए दामों पर था। इसमें ऑफसेट भागीदार अब एचएएल नहीं रह गई थी, बल्कि नई ऑफसेट भागीदार आ गई थी (एक निजी कंपनी जिसे लड़ाकू विमान या विमानों के कल-पुर्जे बनाने का कोई अनुभव नहीं था)। ये फैसले दस अप्रैल को दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में किए गए, न कि दो वार्ताकार दलों के बीच बातचीत के बाद।

छूट और चूक की भरमार

6- साठ हजार करोड़ रुपए की 'भुगतान सुरक्षा प्रक्रिया' में भारत दो आपूर्तिकर्ताओं- दासो और एमबीडीए को भुगतान करेगा, और यह एक तरह से सीधा-सीधा पैसे लुटाने जैसा है। कोई संप्रभुता की गारंटी नहीं होगी, बैंक गारंटी नहीं होगी और यहां तक कि एस्क्रो अकाउंट भी नहीं होगा। यह सारी छूट पीएमओ के निर्देश पर दी गई।

7- भ्रष्टाचार-विरोधी जरूरी धाराएं हटा ली गईं। कमीशन भुगतान मामलों में कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है, एजेंटों की नियुक्ति के खिलाफ भी कोई धारा नहीं है, ईमानदारी को लेकर कोई बात नहीं है, और आपूर्तिकर्ताओं के लेखा-खातों तक कोई पहुंच नहीं होगी। ये सारे फैसले भी पीएमओ ने किए।

8- भारतीय वार्ताकारों के दल (आइएनटी) में तीन विशेषज्ञ सदस्यों- एमपी सिंह, सलाहकार (मूल्य), एआर सुले, एफएम (एअर) और राजीव वेलमा, जेएस एंड एएम (एअर) ने असहमति का एक तगड़ा नोट तैयार किया था। आठ पेज के इस नोट में आइएनटी के बाकी चार सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों को चुनौती दी गई थी।

दिखावटी 'सुप्रीम' ऑडिट

जैसे ही किसी नए तथ्य का खुलासा होता है, सरकार बचाव के लिए तोड़ निकालने में जुट जाती है। सबसे पहले तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बचाव का रास्ता खोजा, लेकिन उसकी यह चाल इसलिए धरी रह गई, क्योंकि फैसले में यह स्वतः स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने विमानों की कीमत और उनकी संख्या घटाने के मामले पर विचार करने से इंकार कर दिया था। जब संसद ने विरोध किया तो सरकार ने लोकसभा में अपने बहुमत के जरिए इसे चुप कराने की कोशिश की, जबकि राज्यसभा में जबर्दस्ती स्थगनों के जरिए चुप कराया गया।

सरकार को उम्मीद रही होगी कि सीएजी की रिपोर्ट उसे बचा लेगी। रिपोर्ट संसद सत्र के आखिरी दिन पेश की गई थी। सरकार को बचाना तो दूर, रिपोर्ट ने इस तथ्य को उजागर कर दिया सरकार ने देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था- कैग की आवाज को दबाने की कोशिश की और इसमें वह सफल भी हो गई। सरकार विमानों के सस्ता होने और जल्द ही उनके मिलने का जो दावा कर रही थी, उसकी भी असलियत इस रिपोर्ट ने दिखा दी।

लगता है कैग ने शुरू में व्यावसायिक ब्योरे में सुधार की मांग का विरोध किया होगा, जैसा कि कैग ने कहा- इसका पूर्व में कोई उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन सरकार के एक कड़े पत्र के बाद इसका कमजोर विरोध खत्म हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि सौदे की तरह ही रिपोर्ट में भी पारदर्शिता नहीं रही, जिसकी कैग से उम्मीद की गई थी।

महत्त्वपूर्ण यह नहीं है कि रिपोर्ट में क्या कहा गया, बल्कि इस पर गौर किया जाना चाहिए जो इसमें नहीं कहा गया है। कैग ने जिन बिंदुओं पर कोई टिप्पणी नहीं कि उनमें ये हैं-

- विमानों की संख्या कम होने (एक सौ छब्बीस के बजाय छत्तीस) पर कीमत में संशोधन के कारण आपूर्तिकर्ताओं को होने वाले बेजा मुनाफे,
- कोई भी भुगतना सुरक्षा प्रक्रिया नहीं होने की सूरत में भारत को होने वाले धन के जोखिम,
- रफाल विमानों के अपूर्ण सौदों के पिछले आर्डर पड़े रहने की सूरत में दासो और एमबीडीए विमानों की समय से आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करेगी,
- भ्रष्टाचार-निरोधी धाराएं हटाने के जोखिम, खासतौर से आपूर्तिकर्ताओं के बैंक खातों तक पहुंच नहीं बनने का मामला,
- सिर्फ थोड़े से विमान मिलने पर वायु सेना की संचालन क्षमता पर पड़ने वाले असर, और
- आइएनटी के तीन सदस्यों द्वारा लिखे गए असहमति के नोट।

रफाल सौदे पर जो धुंध छा गई है, उससे एक बात तो स्पष्ट है- इस बारे में अंतिम शब्द नहीं कहा गया है।

किसानी की दुश्वारियां

दीपक गिरकर

नीति आयोग ने छोटे और सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर पंद्रह हजार रुपए प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष आय समर्थन के रूप में देने की अनुशंसा की थी। पर अंतरिम बजट में सरकार ने इन्हें छह हजार रुपए सालाना की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को तीन हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के लिए आबंटन में वृद्धि, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को फसल ऋण पर दो फीसद ब्याज सब्सिडी और फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर अतिरिक्त तीन फीसद ब्याज सब्सिडी की घोषणा की गई है। देश में ऐसी योजनाएं कुछ राज्यों में पहले से मौजूद हैं। तेलंगाना में छोटे और सीमांत किसानों को चालीस हजार रुपए वार्षिक मिल रहे हैं। ओडिशा में सभी किसानों को पांच हजार रुपए सालाना मिल रहे हैं। इसके अलावा ओडिशा में फसल बुवाई के लिए पच्चीस हजार रुपए और भूमिहीन परिवारों को साढ़े बारह हजार रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से मिल रहे हैं। झारखंड में भी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ पांच हजार रुपए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अंतरिम बजट में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छह हजार रुपए बहुत कम है। तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के अलावा अन्य राज्य सरकारों को भी छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को प्रत्यक्ष आय समर्थन योजना लागू करनी चाहिए।

देश में पचासी फीसद छोटे और सीमांत किसान हैं। इन किसानों की छोटी जोत होने के कारण इनकी उत्पादन लागत औसत लागत से काफी अधिक आती है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी खेती के विभाजित होने से जोत का आकार घटता जा रहा है। खेतों का आकार छोटा होने से कृषि उत्पादन और फसलों से होने वाली बचत में कमी आ रही है। छोटे और सीमांत किसान खेती के लिए कृषि उपकरण और कृषि मशीनरी किराए पर लेते हैं। सिर्फ दस फीसद बड़े किसान न्यूनतम समर्थन मूल्यों का फायदा उठाते हैं। छोटे और सीमांत किसान फसल आते ही अपनी उपज कम कीमत पर बेचने को मजबूर होते हैं, क्योंकि वे कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। साल भर ये अपने गुजारे के लिए कृषि उत्पाद बाजार से खरीदते रहते हैं, जो इन्हें समर्थन मूल्य में वृद्धि की वजह से महंगे मिलते हैं।

छोटी जोत वाले किसानों के पास खेती के पर्याप्त साधन, सिंचाई की व्यवस्था आदि का अभाव होता है और इस सबके लिए उन्हें बड़े किसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। छोटे किसानों के लिए खेती के साधन जुटाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जैसे-जैसे खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, किसानों को होने वाला फायदा भी कम हो रहा है। हर पांच साल में कृषि क्षेत्र में एक करोड़ छोटे किसान जुड़ रहे हैं। अगर यह दर बरकरार रही तो आने वाले समय में कृषि क्षेत्र के हालात बेकाबू हो सकते हैं।

लघु किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है पूंजी की कमी। अपनी घरेलू जरूरतों से लेकर कृषि की लागत तक उन्हें पैसा चाहिए और इसके लिए वे साहूकार और किसान क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से चूंकि सरलता से पैसा मिल जाता है, इसलिए इसका उपयोग वे कृषि की जगह अपने सामाजिक और घरेलू जरूरतों की पूर्ति में लगा देता है। पैसा खर्च होने के बाद किसानी की लागत के लिए साहूकारों के चुंगल में फंस जाता है। आज भी अधिकतर खेती मानसून के सहारे चलती है। मानसून के रूठ जाने पर सूखा, कीमतों में वृद्धि, कर्ज का अप्रत्याशित बोझ, बैंकों के चक्कर, बिचौलियों और साहूकारों के घेरे में फंस कर छोटा किसान या तो जमीन बेचने पर मजबूर है या आत्महत्या पर।

इस तरह छोटे और सीमांत किसान अपनी कृषि भूमि बेच कर भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों की श्रेणी में आते जा रहे हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी छोटे और सीमांत किसानों की जमीन कम होती और कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ती चली गई। देश में लगभग 54.6 फीसद कामगार कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। गांवों में लगभग बीस करोड़ परिवारों में से करीब चौवन फीसद श्रमिक हैं। आधिकारिक आकलनों में प्रति तीस मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, इसमें छोटे, सीमांत किसान और भूमिहीन श्रमिक हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर आत्महत्या के मामलों की सघन जांच की जाए, तो ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा निकलेगी, जो मजदूर और शोषित वर्ग के हैं। उनका जमीन पर स्वामित्व तो है, लेकिन उनकी जमीन किसी साहूकार या बड़े किसान के पास गिरवी रखी है और वे बटाईदार का काम करते हैं।

पिछले दस वर्षों में लगभग तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है, जिनमें से अधिकतर सीमांत किसान और कृषि मजदूर थे। कृषि मजदूर सबसे शोषित और उत्पीड़ित वर्गों में से एक हैं। कृषि क्षेत्र में ग्रामीण श्रमिक देश के लिए बड़ी चुनौती है। मनरेगा में सभी श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता और जिनको मिलता है उन्हें भी कुछ ही दिनों का रोजगार मिलता है। मनरेगा में असमय भुगतान और हर समय काम न मिलने की वजह से ग्रामीण भूमिहीन परिवार शहरों में जाकर मजदूरी करने लगे हैं।

कृषि

> अभी तक कृषि क्षेत्र की समस्याओं का बेहतर समाधान खोजने का प्रयत्न नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण सरकारों की इच्छाशक्ति में कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग-धंधों की स्थापना की जानी चाहिए।

सरकार ने अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तीन हजार रुपए प्रतिमाह की जिस पेंशन योजना की घोषणा की है, उसका लाभ श्रमिकों को साठ वर्ष की आयु के बाद ही मिलेगा। इस योजना के लिए श्रमिकों को प्रतिमाह सौ रुपए का अंशदान करना होगा। नीति आयोग और सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों की माली हालत पर विचार नहीं किया। भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों की मासिक आय के साधन तलाशने के लिए भी एक समग्र नीति बननी चाहिए।

अभी तक कृषि क्षेत्र की समस्याओं का बेहतर समाधान खोजने का प्रयत्न नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण सरकारों की इच्छाशक्ति में कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग-धंधों की स्थापना की जानी चाहिए। गांवों में स्थानीय उत्पाद को ध्यान में रखते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर नीति आयोग और सरकार का ध्यान होना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में न के बराबर है। अगर सरकार की वास्तविक मंशा है कि सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए, ग्रामीण श्रमिकों को गांवों में ही रोजगार मिल जाए, ग्रामीण युवा रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन न करे, तो सरकार को सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय फसल को ध्यान में रखते हुए कृषि आधारित ऐसे उद्योगों की स्थापना करनी होगी, जिसमें किसानों की फसलों की खपत हो सके, जैसे फ्लोर मिल, तेल मिल, राइस मिल, कॉटन मिल और छोटे कुटीर उद्योग जैसे टमाटर सॉस, जैम, पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, चिप्स, सिवइयां, अचार-मुरब्बा आदि और इन उद्योगों में स्थानीय ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी देना होगा। इससे किसानों को उनकी फसल के उचित दाम भी मिलेंगे और कृषि आधारित उद्योगों में उनके युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध हो जाएंगे। इन ग्रामीण उद्योगों में जो अंतिम उत्पाद तैयार होंगे उनकी विपणन की सारी व्यवस्था इन ग्रामीण युवाओं के हाथों में ही देने से किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हो पाएगा।

अभी तक ग्रामीणों और किसानों के कल्याण की जो योजनाएं बनाई गई हैं और जिस तरह उनका क्रियान्वयन किया गया है, वे सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रख कर ही किए गए हैं। जब तक कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक कृषि कराहती रहेगी, छोटे, सीमांत किसान और भूमिहीन ग्रामीण या तो गांवों से पलायन करते रहेंगे या आत्महत्या करते रहेंगे।

यह आतंकवाद नहीं, युद्ध है

जब तक हमारे शासक स्वीकार नहीं करते कि पुलवामा जैसे हमले आतंकवाद नहीं, युद्ध का हिस्सा हैं, तब तक हमारे बहादुर जवान शहीद होते रहेंगे। जिन चौवालीस सीआरपीएफ जवानों को उस कायर फिदाईन ने मारा पिछले हफ्ते वे शायद न मरते अगर जानते कि युद्ध के मैदान में खड़े हैं और दुश्मनों के वार के लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। हमले के बाद सुनने को मिलीं हमें वही बातें, जो अक्सर सुनने को मिलती हैं ऐसे हमलों के बाद। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। यही बात गृहमंत्री ने कही। सिर्फ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कबूल किया कि खुफिया संस्थाओं की गलती थी कि एक गाड़ी, जिसमें इतना असला था, आसानी से पहुंच पाई सीआरपीएफ के इतने बड़े काफिले के पास।

अब भी लेकिन हम इसको आतंकवाद ही कह रहे हैं, युद्ध नहीं। अब भी हमारे शासक मान कर चल रहे हैं कि युद्ध होता है सीमाओं पर, शहरों में नहीं। सो, जब उड़ी में सैनिक शिविर पर इसी जैश-ए-मोहम्मद ने हमला किया था 2016 में तो प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। हम सब खुश हुए यह सोच कर कि नरेंद्र मोदी नए किस्म के राजनेता हैं और पाकिस्तान की ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देंगे। लेकिन उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कभी स्पष्ट नहीं किया मोदी ने कि उनकी पाकिस्तान को लेकर नीति क्या है। हां, इतना जरूर कहते हैं बार-बार कि बातचीत तभी शुरू होगी दोनों देशों के बीच, जब भारत की भूमि पर आतंकवादी हमले रुक जाएंगे। पर अभी तक स्वीकार नहीं किया है उन्होंने कि यह आतंकवाद नहीं युद्ध है। ऐसा युद्ध, जिसकी तैयारी हम अभी तक कर नहीं पाए हैं, क्योंकि अब भी हम इसको आतंकवाद ही समझ रहे हैं।

सच तो यह है कि पाकिस्तान बहुत पहले जान गया था कि पुराने किस्म के युद्ध अब नहीं हो सकते हैं दोनों देशों के बीच, क्योंकि परमाणु युद्ध हो जाने का खतरा है। सो, पाकिस्तानी सेना ने बहुत पहले से तैयार किए हैं मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे जिहादी जरनैल, जो हैं तो पूरी तरह असली सैनिक, लेकिन इनको जिहादी कहा जाता है। इनकी संस्थाओं को प्रशिक्षित करती है पाकिस्तानी सेना, इनके हथियार भी सेना से आते हैं और इनके हमलों के लिए पैसा भी सेना देती है।

भारत ने बहुत देर लगा दी है इस नए युद्ध की तैयारी करने में। तैयार होते हम, तो मौलाना मसूद अजहर को क्या पांच साल कैद रखते भारत में बिना दंडित किए? जब आइसी 814 जहाज हाइजैक हुआ था 1999 के आखिरी दिनों में और हाइजैक करने वालों ने मौलाना मसूद और उमर शेख की रिहाई मांगी यात्रियों के बदले, तब याद आया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिहादी सरगना हमारे पास है। रिहा होने के फौरन बाद इसको हमने क्यों नहीं मारा? क्या इसलिए कि हमारे पास ऐसा करने की ताकत नहीं है? हमारी सेना ने नहीं तैयार की हैं ऐसी संस्थाएं, जो जैश-ए-मोहमद जैसी संस्थाओं का सामना कर सकती हों?

यह जिहादी मौलाना रिहा होने के बाद इतने आराम से रहने लगा पाकिस्तान में कि उसने एक किताब भी लिखी, जिसमें उसने लिखा कि जब भारत से उसको कंधार ले जा रहे थे भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह, तो उन्होंने उसको खाना और पानी पेश किया। लेकिन उसने लेने से इंकार किया, क्योंकि 'भारत के पानी की एक बूंद भी मेरे गले से नहीं उतर सकती है।' किताब लिखने के बाद इस मौलाना ने अपनी संस्था जैश-ए-मोहम्मद द्वारा हमारी संसद पर हमला करवाया दिसंबर 2001 में। हमने अफजल गुरु जैसे छोटे-मोटे सहायक को तो फांसी पर लटका दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने सारी साजिश रची थी, उसको कुछ नहीं कर पाए हैं। और शायद पुलवामा हमले के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे।

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

> सच तो यह है कि पाकिस्तान बहुत पहले जान गया था कि पुराने किस्म के युद्ध अब नहीं हो सकते हैं दोनों देशों के बीच, क्योंकि परमाणु युद्ध हो जाने का खतरा है। सो, पाकिस्तानी सेना ने बहुत पहले से तैयार किए हैं मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे जिहादी जरनैल, जो हैं तो पूरी तरह असली सैनिक, लेकिन इनको जिहादी कहा जाता है।

पहले जब कांग्रेस के सेक्युलर प्रधानमंत्रियों का राज था, उनसे उम्मीद भी करना बेकार था कि वे इस नए युद्ध के लिए हमारे सैनिकों को प्रशिक्षित करेंगे। जब 26/11 वाले हमले के बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी किताब का विमोचन कर सकता है, जिसका शीर्षक था '26/11 : आरएसएस की साजिश' तो कांग्रेस से क्या उम्मीद की जा सकती है। जब राहुल गांधी कह सकते हैं कि उनको जिहादी आतंकवाद से ज्यादा खतरा महसूस होता है हिंदू आतंकवाद से, तो बेकार है कांग्रेस से देश को ज्यादा सुरक्षित करने की उम्मीद।

मगर प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद जरूर थी कि वे ऐसी नीतियां बनाएंगे देश की सुरक्षा को लेकर, जिसमें हम भी ऐसे दस्ते तैयार करेंगे, जो पुलवामा जैसे हमलों के बाद मसूद अजहर जैसे दरिंदों को ढूंढ़ निकाल कर जान से मारने की काबिलियत रखते हों। बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे दस्ते अभी तक तैयार नहीं हुए हैं और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आम चुनावों को कुछ ही हफ्ते बाकी हैं।

सो, फिलहाल हम सिर्फ आशा यह कर सकते हैं कि मोदी जल्द से जल्द फैसला लेंगे पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते तोड़ने का। इस्लामाबाद में क्या फायदा है भारतीय दूतावास का, अगर ऐसे हमले हो रहे हैं हमारी भूमि पर? तिजारत का भी कोई फायदा नहीं है ऐसे माहौल में, सो जैसे हमने फैसला किया था बहुत पहले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने का, अब फैसला जरूरी है सारे रिश्ते समाप्त करने का, जब तक पाकिस्तान हमारी धरती पर पुलवामा जैसे हमले बंद करने का आश्वासन नहीं देता है किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के सामने। बहुत खून बहाया है हमारे बहादुर जवानों ने एक ऐसे युद्ध में, जिसको अभी तक हमने युद्ध का नाम ही नहीं दिया है।

दो मिनट का मौन

सस्ती चुनावी राजनीति की बहसें चल रही थीं। लेकिन एक क्षण में सारा मंजर बदल गया। बहसें बदल गईं। राजनीति बदल गई और गुस्सा छा गया!

जम्मू कश्मीर के पुलवामा-अवंतीपोरा की सड़क। गाड़ियों का एक लंबा काफिला आ रहा है। सैनिक ड्यूटी पूरा करके लौट रहे हैं कि अचानक एक फिदाइन हमला होता है और कहानी बदल जाती है। पूरी बस यानी चौवालीस जवानों के चिथड़े उड़ जाते हैं। बस लोहे की एक मुड़ी-तुड़ी ठठरी बनी जाती है। सैनिकों के चिथड़े दूर तक फैल जाते हैं। एक सैनिक बस का एक टुकड़ा बस के ढेर की ओर फेंक देता है।

पहले दृश्य सभी कुछ कहते थे। सैंतीस जवानों से भरी गाड़ी सड़क के एक ओर लोहे का पिंजर बन कर पड़ी थी। हर खबर चैनल इस हमले को कवर कर रहा है। दर्जनों बुरी तरह घायल हैं। रिपोर्टर बताते हैं कि किस तरह एक एसयूवी में तीन सौ पचास किलो आरडीएक्स फिदाइन दस्ते में बदल गया। इसके पीछे कौन था। यह सीआरपीएफ के सैनिकों की बीच अचानक कैसे घुस पड़ी। क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई? तरह-तरह के सवाल उठते रहे।

वही कुख्यात आतंकवादी हाफिज हमले के संदर्भ की तरह छाया रहा। एक चैनल उसके जहर भरे भाषणों के अंश दे रहा है। एक एंकर उनसे हिसाब मांग रहा है, जो आतंकवादी अफजल के अंतिम अवशेषों को लौटाने की बातें करते थे।

पीडीपी अध्यक्ष आती हैं और हमले के बारे में बताती हैं, लेकिन इस हमले को 'कंडेम' नहीं करतीं। एंकर ऐसे 'कंडेम' न करने वालों को 'कंडेम' करता है।

एक एंकर चिल्लाता है कि इन 'लॉबिस्टों' का 'सिक्यूरिटी कवर' कब हटेगा? वह हिसाब लगा कर बताता है कि हर बड़े 'लॉबिस्ट' नेता की सुरक्षा पर सात करोड़ रुपए खर्च बैठता है और ये उनके कवच बनते हैं, इनका कवच खत्म करो।

हर एंकर गुस्से में है। चैनलों में गुस्सा भरा है। रिपोर्टर तक गुस्से में हैं। यह सबसे बड़ा हमला है। कुछ एंकर तो अभी हिसाब कर देना चाहते हैं। एक चैनल 'सर्जिकल स्ट्राइक-टू' की मांग कर रहा है।

एक चैनल पर जेके के राज्यपाल आते हैं और हमले की निंदा करने के अलावा व्यवस्था में चूक की बात भी करते हैं।

यह उड़ी के हमले से बड़ा हमला है, जब उड़ी के बदले सर्जिकल की गई, तो इसके बदले क्या करेंगे? यह एक आम मांग बन गई है।

वही-वही दृश्य दुहरते हैं। पहले हमला होता है, फिर चूक की खबर आती है, फिर 'लॉबिस्ट' ठुंकते हैं, फिर 'राजनीति न करें' की मांग होती है, फिर राजनीति होने लगती है।

लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखता। सभी सावधान हैं।

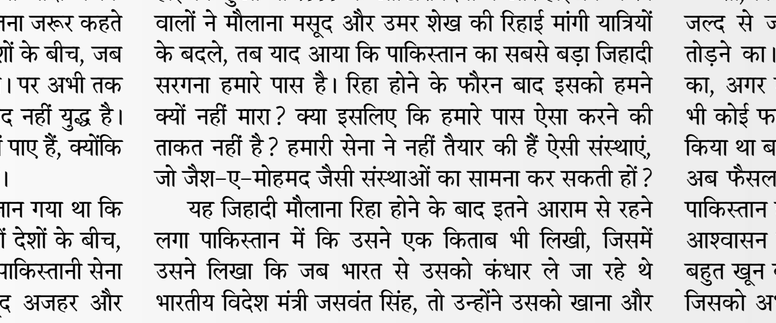

बाखबर

■ सुधीश पचौरी

> जिनके लोग मारे गए हैं उनका रो-रो कर बुरा हाल है। गांवों-कस्बों में रहती पत्नियां, बच्चे अचानक अनाथ हो गए हैं। वे बुरी तरह रोते-बिलखते दिखते हैं। यह सब इतनी बार दिखाया जाता है कि सबका दुख हमले के दृश्यों में खप जाता है।

गृहमंत्री मौका-ए-मुआयने पर जाने वाले हैं।

एक चैनल के विशेषज्ञ कहते हैं कि पांच किलो आरडीएक्स एक बड़े मकान को तबाह कर सकता है, तो तीन सौ पचास किलो आरडीएक्स मुहल्ले भर को उड़ा सकता है।

जैश-ए-मुहम्मद हमले का श्रेय लेता है और अगली बार हाफिज सईद के चित्र पर एक चैनल गोली चलवाने लगता है- ठांय ठांय ठांय...

अगली सुबह पीएम की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक होने की खबर है। हर चैनल अनुमान लगा रहा है कि क्या फैसला करने वाले हैं। एक अनुमान के अनुसार राज्यपाल को बदल कर रिटायर्ड सैनिक अफसर जेके भेजा जा सकता है। बैठक खत्म होती है, तो पीएम क्षुब्ध स्वर में संबोधित करते हैं : मैं आतंकवादियों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। सैनिकों के रक्त की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा... एंकर व्याख्या करती है कि अब देखना है कि कब क्या किया जाता है।... क्या इस व्याख्या की जरूरत थी?

जेटली बताते हैं कि पाकिस्तान को दिया गया तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया गया है। गृहमंत्री कल सर्वदलीय बैठक को संबोधित करेंगे।

जिनके लोग मारे गए हैं उनका रो-रो कर बुरा हाल है। गांवों-कस्बों में रहती पत्नियां, बच्चे अचानक अनाथ हो गए हैं। वे बुरी तरह रोते-बिलखते दिखते हैं। यह सब इतनी बार दिखाया जाता है कि सबका दुख हमले के दृश्यों में खप जाता है।

उधर सब खुफिया रहता है, इधर के चैनल हर चीज को खोल कर रख देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा तो ऐसे कर रहे हैं कि मानो एंकर ही करने वाले हैं। एक चैनल पर एक जवान कांस्टेबल मनोज कुमार चौवालीस की जगह चार सौ सिर काटने की बात कहता दिखाया जाता है। सेना के हाथ खुले छोड़ देने चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ करना होगा, तो उनको बचाने वाले बेगुनाहों को भी मारना होगा। जहां भी पत्थरबाज मिले, उसे वहीं गोली से उड़ा देना चाहिए। फिर वह पीएम को संबोधित करने लगता है कि वे फिर से सर्जिकल स्ट्राइक-टू कर दें... एंकर कहती है कि यह भावना दरअसल, पूरे देश की है।

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष प्रेस को संबोधित करने लगते हैं कि यह एक भयानक त्रासदी है। आतंकवाद देश को बांटना चाहता है, लेकिन कोई भी शक्ति इस देश को तोड़ नहीं सकती। पूरा विपक्ष सुरक्षाबलों और सरकार के साथ खड़ा है। यह हमला हिंदुस्तान की आत्मा पर हुआ है, हम उनके और सरकार के साथ हैं। जिनने किया है उनको यह न लगे कि वे देश को जरा भी चोट पहुंचा सकते हैं। कुछ दिनों तक हमें अब कुछ और विचार नहीं करना... आज पूरी कांग्रेस पार्टी तथा विपक्ष जवानों और सरकार के साथ खड़े हैं।...

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि आज का दिन शोक का दिन है। चालीस जवान मारे गए हैं। हम उनके परिवारों के साथ हैं। हम आतंकवाद के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। यह वक्त विवादास्पद मुद्दे उठाने का नहीं है।

दो मिनट का मौन।